भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 41
जिसका उत्तर बृहस्पतिवार, 23 अप्रैल, 2015 को दिया जाना है

भारी उद्योगों को स्थापित करने के लिए नीति

41. श्री हुसैन दलवई:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारी उद्योगों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को स्थापित करने के संबंध में अब तक सरकार की क्या नीति है;

(ख) क्या सरकार क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने के लिए पिछड़े क्षेत्रों में इन उद्योगों को स्थापित करने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क) से (ग): उद्योग राज्य का विषय है। अतः, भारी उद्योगों की स्थापना के लिए भारी उद्योग विभाग द्वारा कोई नीति नहीं बनाई जाती है। भारी उद्योग विभाग की भूमिका इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों तक सीमित है। भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम वाणिज्यिक महत्व के आधार पर अपनी इकाइयों को स्थापित करते हैं। तथापि, कई राज्यों द्वारा उद्योगों के विकास और वृद्धि के लिए प्रोत्साहन और योजनाएं तैयार की गई हैं। केन्द्र सरकार भी वित्त मंत्रालय के माध्यम से संपूर्ण देश में उद्योगों की वृद्धि के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संरचना में प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है।

****